The Bill was, by leave, withdrawn.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Now, we will take up the Constitution (Amendment) Bill, 2008 to amend articles 85 and 174. Shri Mahendra Mohan to move the motion.

The Constitution (Amendment) Bill, 2008 (to amend articles 85 and 174)

SHRI MAHENDRA MOHAN (Uttar Pradesh): Sir, I move that the Bill to amend articles 85 and 174 of the Constitution of India to be taken into consideration.

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं पिछले तीन साल से राज्य सभा में रहते हुए, जो हालात देख रहा हूं, उसको ध्यान में रखते हुए, यह विधेयक लाया हूं। मैं इस विधेयक के माध्यम से सदन का ध्यान एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय की तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं। विधेयक में प्रस्तुत संशोधन मामूली प्रतीत होते हैं, लेकिन इससे संबंधित पहलू बहुत ही गंभीर हैं। मैंने प्रस्ताव किया है कि संविधान के अनुच्छेद 85 एवं 174 में संशोधन करके लोक सभा और राज्य सभा के लिए बैठकों की अवधि कम से कम 120 दिन तथा विधान सभाओं की अवधि एक साल में कम से कम 60 दिन की जाए।

उपसभाध्यक्ष महोदय, पिछले साल लोक सभा की 46 और राज्य सभा की 46 बैठकें हुईं। यह समय 1952 से लेकर अब तक का सबसे कम समय बैठकों का रहा है। बैठकों की अवधि लगातार कम हो रही है, जिसका सीधा असर हमारे संसदीय कार्य पर पड़ा रहा है। कार्यपालिका की सीधी जिम्मेदारी विधायिका के प्रति है जो इसकी तमाम गतिविधियों की समीक्षा करती है तथा संसदीय तंत्र में उपलब्ध प्रावधानों जैसे प्रश्न-प्रहर, विशेष उल्लेख, अल्पकालिक चर्चा, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर बहस के माध्यम से देश में उत्पन्न स्थिति, आर्थिक विषयों तथा अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर देश की जनता की भावनाओं की अभिव्यक्ति करती है। अगर सत्र कम समय चलता है तो विभिन्न विषयों पर चर्चा नहीं हो पाती है। उसमें भी अधिकतर समय शोरगुल तथा व्यवधान में व्यतीत हो जाता है।

1949 में जब संविधान स्वीकार हुआ उस समय डॉ0 भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था, "अगर हमें प्रजातंत्र चलाना है तो हमें क्या करना चाहिए ? मेरी समझ से हमें संविधान के द्वारा प्रदत्त शक्तियों और अधिकारों का इस्तेमाल अपने सामाजिक और आर्थिक लक्ष्यों की पूर्ति के लिए करना चाहिए। जब हमारे पास संविधान और संवैधानिक अधिकार नहीं थे, तो उस समय असंवैधानिक तरीकों का प्रयोग जायज था।" डॉ0 अम्बेडकर ने आगे फिर कहा है, "संविधान का कार्यकरण संविधान की प्रकृति पर पूर्णतः निर्भर नहीं है। संविधान केवल राज्य के अंगों, जैसे विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका की व्यवस्था ही कर सकता है। राज्य के इन अंगों का कार्यकरण वस्तुतः जिन कारकों पर निर्भर करता है, वे हैं जनता तथा उसकी इच्छाओं और राजनीति को कार्यान्वित करने के लिए, उनके द्वारा गठित राजनैतिक दल, कौन बता सकता है कि भारत की जनता और उनके दलों का व्यवहार कैसा होगा?"

डॉ0 अम्बेडकर के इन दोनों वक्तव्यों को अगर हम आज की विधायिका के कार्यकरण, उसके द्वारा सांसदों को प्रदत्त अधिकार, उनका इस्तेमाल, संसद की महत्ता तथा आम आदमी की उससे अपेक्षा के संदर्भ में देखें, तो हमें पतन की स्थिति साफ दिखाई देती है। स्वतंत्रता के पहले जब हमारे पास संवैधानिक अधिकार नहीं थे, विधायिका में भारतीयों का प्रतिनिधित्व नहीं था, उस समय हमारे पूर्वजों ने पूर्ण स्वराज अधिकार और संविधान के लिए संघर्ष किया।

भारत के प्रथम प्रधान मंत्री ने संसद के केन्द्रीय कक्ष से भारत की आजादी का उद्घोष किया। पंडित जी का मध्य रात्रि का उद्घोष भारतीय जन मानस में संसद की प्रतिष्ठा और महत्ता को केन्द्रित करने के लिए था।

आज जब संसद है, संसद में प्राप्त अधिकारों से आम आदमी की अपेक्षाओं को हम प्रतिध्वनित कर सकते हैं, देश का हर नागरिक हमें आशा भरी नजरों से देख रहा है। उस समय हम अपने कर्तव्यों का सही पालन नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों समान रूप से जिम्मेदार हैं।

आज संसद का महत्व वह नहीं रहा है जो पंडित नेहरू के समय में हुआ करता था। पंडित नेहरू जी ने हर महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के दौरान उपस्थित रहते थे। यहां तक कि जब वह बीमार होते थे, तब भी डाक्टरों की आराम करने की सलाह को न मानकर भी यदि आवश्यक विषय होता था, महत्वपूर्ण चर्चा होती थी, तो वह उस दौरान संसद में आकर अपना योगदान देते थे और संसद की बहस को सुनते थे।

पंडित नेहरू और उनके समकालीन राजनीतिज्ञों ने संसदीय संस्थाओं का केवल निर्माण ही नहीं किया, बल्कि उसे गरिमा भी प्रदान की और हमेशा उन्हें अपने व्यक्तित्व से ऊपर रखा। एक बार विधेयक पर चर्चा के दौरान पंडित नेहरू ने राजा जी के संशोधन को मानने से इनकार करते हुए कहा, 'राजा जी, बहुमत हमारे साथ है।' राजा जी ने उसका जवाब दिया, 'पंडित जी, तर्क हमारे साथ है।' पंडित जी ने तुरंत संशोधन स्वीकार कर लिया। आज जो स्थितियां हैं, अगर सही तर्क भी होता है, सही संशोधन भी होते हैं, तो यहां पर उन्हें स्वीकार करने में लोगों को बड़ा कष्ट होता है। एक बार पंडित जी बैठक से उठकर जाने लगे, तो किसी सांसद ने टोक कर कहा कि प्रधान मंत्री आसन को पीठ दिखा रहे हैं। उन्होंने तुरन्त इसके लिए क्षमा मांगी। यह उस वक्त महत्व था, ये उस वक्त की सीमाएं थीं और इस प्रकार अनुशासन के साथ संसदीय परंपराएं चल रही थीं। ऐसे महानुभावों के साये में पल्लवित भारतीय संसदीय परंपरा आज पतन की स्थिति में है। सरकार सत्रों का समय लगातार कम करती जा रही है, बहस से कतराती जा रही है, महत्वपूर्ण विधेयक बिना चर्चा के पास हो जाते हैं और केवल जीरो ऑवर का ही महत्व बढ़ रहा है, क्योंकि उसमें हल्ला-गुल्ला मचाया जा सकता है। प्रश्नों के पूरे उत्तर नहीं आते हैं, महत्व के विषयों पर बहस नहीं हो पाती है। यह स्थिति बहुत ही चिंताजनक है। इससे भी अधिक चिंता का विषय है, संसद का बार-बार हंगामों के बीच स्थगित होना। कई बार यह पहले ही निश्चित हो जाता है कि आज संसद को चलने दिया जाएगा या नहीं चलने दिया जाएगा। हर पार्टी में इस तरह के निर्देश दे दिए जाते हैं कि आज संसद को चलने दिया जाएगा अथवा नहीं चलने दिया जाएगा, जो कि बहुत ही गलत है। ऐसी स्थिति में संसद की एक ऐसी संस्था के होने की छवि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जिसे लोकतंत्र में एक जवाबदेही वाली संस्था के रूप में जाना जाता है। इसका लोकतंत्र पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। महोदय, अभी हमारे सभापति महोदय, ने भी मुम्बई में 4 फरवरी, 2008 को चौदहवें अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन के उद्घाटन के अवसर पर कहा था - 'पतन का संकेत साफ झलक रहा है। हमारे विधान मंडलों को उपलब्ध कराए गए साधन या तो निष्प्रभावी कर दिए गए हैं या वे सही ढंग से कार्य करने के योग्य नहीं रह गए हैं। आज एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण चिंता की बात सार्वजनिक कल्याण का उपाय करने और प्रभावकारी कानून तथा सार्वनिक नीति तैयार करने में योगदान करने में समर्थ प्रभावी संस्था के रूप में हमारे विधान मंडलों की घटती विश्वसनीयता है। आवश्यकता इस बात की है कि विधान मंडलों में अधिक से अधिक कार्य निष्पादन के लिए उनके दिन प्रतिदिन के कार्यकरण की समीक्षा की जाए।'

इसके लिए सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि वह संसद की गरिमा को बनाए रखने में सभी दलों को साथ में लेकर चले। हमारे सभापति महोदय ने अपने भाषण में यह भी कहा - विधायिका के विचार-विमर्श करने संबंधी कार्यों में निश्चित रूप से गिरावट आई है। इसके लिए सदन के सभी पक्ष जिम्मेदार हैं। सत्ता पक्ष जन-सरोकार के मुद्दों पर ठोस चर्चा करने से बचता है। विपक्ष इन मुद्दों को बढ़ा-चढ़ाकर उल्लेख करने के लिए ही तथाकथित शून्य काल का इस्तेमाल करने को प्राथमिकता देता है। ...(व्यवधान)..

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Mr. Mohan, while moving, you need not give a long speech because you will have the right to speak when you reply to the debate.

श्री मोहन सिंह : I am only quoting what is said already. इस प्रकार विचार-विमर्श व्यर्थ का खेल बनकर रह जाता है। नीतियां जनता को उत्पाद की तरह परोस दी जाती हैं। निर्वाचकगण को इस प्रक्रिया के बारे में पता नहीं चल पाता।

महोदय, हमें जनता के बीच में संसद और संसदीय कार्य के बारे में विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए सत्र के दिनों की बढ़ोत्तरी करनी चाहिए, ताकि लोक महत्व के विषयों पर अर्थवान बहस हो सके। पिछले साल का मानसून सत्र समाप्त हो गया। यह संसदीय इतिहास में पहली बार हुआ है। यह हमारी संसदीय परंपरा का सबसे बड़ा अपमान था। तकनीकी तौर पर बजट सत्र फरवरी से मई के बीच, मानसून सत्र जुलाई से सितम्बर के बीच में तथा शरदकालीन सत्र नवम्बर से दिसम्बर के मध्य होता है। 22 अप्रैल, 1955 को लोक सभा की GPC (General Purpose Committee) ने तीनों सत्रों के लिए तारीखें निश्चित की थी और उसकी सिफारिश की थी, जिसे कैबिनेट ने स्वीकार भी किया था, लेकिन पिछले मानसून सत्र का कैलेंडर से गायब हो जाना, एक आश्चर्यजनक बात थी। विश्वास मत के लिए 21 और 22 जुलाई को दो दिन का सत्र हुआ और यह बात सामने आई कि शायद 11 अगस्त से सत्र हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सन् 2008 में राज्य सभा की केवल 46 बैठकें हुईं और 2007 में 65 बैठकें हुई थीं। यदि हम पुराने इतिहास पर जाएं, तो उस वक्त हमारी जनसंख्या कम थी, कार्य भी कम होते थे, तब हमारी समस्याएं ज्यादा होती थी। अगर हम 1952 से लेकर आज तक एक तुलनात्मक अध्ययन करें, तो पाएंगे कि संसद की बैठकों में सतत् गिरावट आई है। पहली लोक सभा में (1952-57) 677 बैठकें हुई थीं।

...3784 घंटे कामकाज हुआ। इस दौरान राज्य सभा में (1952-57) के बीच 565 बैठकें हुई। 1952-57 में बैठकों का औसत 135 प्रतिवर्ष था, जो अब घटकर 46 रह गया है। 1956 में लोकसभा की 151 बैठकें हुईं तथा राज्यसभा की 113 बैठकें हुईं, यही एक रिकार्ड है।

राज्यसभा में 1952-61 के पहले दशक में बैठकों का वार्षिक औसत 90.5प्रतिशत था जो 1992-2001 के दौरान 20 प्रतिशत गिरकर 71.3 प्रतिशत रह गया। लोक सभा के मामले में 34 प्रतिशत की गिरावट रही।

1952-61 के दशक में संसद द्वारा पारित विधेयकों की संख्या वार्षिक औसत 68 था, जो कि 1992-01 के दौरान घटकर 49.9 प्रतिशत रह गया। ग्यारहवीं लोकसभा में लगभग 5.28 प्रतिशत कार्य समय व्यवधान के कारण नष्ट हुआ। 12 वीं लोकसभा में यह बढ़कर 10.66 प्रतिशत, 13वीं में 19 प्रतिशत और 14 वीं लोकसभा में 21 प्रतिशत समय बरबाद हुआ।

2007 में लोकसभा ने 41 प्रतिशत विधेयक, जिसमें वित्त विधेयक भी शामिल है, बिना किसी या थोड़ी सी बहस के बाद पारित कर दिए।

तीन सालों में बिना बहस के पारित विधेयकों का प्रतिशत 17 प्रतिशत से बढ़कर 41 प्रतिशत हो गया। इस दौरान जिन विधेयकों पर चर्चा हुई, उनका प्रतिशत 39 से घटकर 24 रह गया।

2007 में ही 32 प्रतिशत विधेयक, जिसमें वित्त विधेयक भी शामिल है, बिना किसी बहस के पारित हो गए। 2005 से बिना बहस के विधेयकों के पास कराने की प्रवृत्ति 26 प्रतिशत से बढ़कर 32 प्रतिशत हो गई।

इन मामलों में राज्य विधान सभाओं की स्थिति बहुत ही खराब है। जहां पूरे साल में 20 से लेकर 50 दिनों की बैठकों होती हैं। कर्नाटक में जहां एक बार 1974 में 97 दिनों की बैठकें हुईं, वहीं पिछले साल सिर्फ 20 दिनों के आसपास बैठकें हुईं। पूर्वोत्तर राज्यों की स्थिति और भी खराब है। वहां पर तो अक्सर दो या तीन दिनों का ही सत्र चलता है।

अब हम एक दृष्टि कुछ विदेशी संसदों पर डालते हैं। जहां पर हमसे कम समस्याएं हैं, कम जनसंख्या है, कम कार्य है, लेकिन वहां पर हमसे अधिक बैठकें की जाती हैं। युनाइटेड किंगडम, जो कि भारत की तुलना में

काफी छोटा देश है, वहां पर कई बार 200 से ज्यादा एक साल में बैठकें हुईं। 1966-67 में वहां 246, 1979-80 में 244, 1983-84 में 213, 1987-88 में 218, 1992-93 में 240, 1997-98 में 241, 2001-02 में 201 और 2005-06 में 208 बैठकें हुईं।

कनाडा की बात कही है। मैंने कनाडा की संसद का 2009 का कैलेण्डर देखा। जिसमें 2009 में लिए 155 दिनों की बैठकों का प्रावधान है, न्यूजीलैण्ड में 2009 के कैलेण्डर के लिए लगभग 92 दिनों की बैठकों का प्रावधान है, जबकि उस देश से बड़े हमारे यहां के प्रदेश हैं। दक्षिण अफ्रीका में प्रतिवर्ष बैठकों का औसत 104 है, केन्या में 88 तथा अमेरिकी कांग्रेस में 150 ।

सभापति महोदय, मैं ये बातें आपके सामने केवल इसलिए ला रहा हूं, क्योंकि अगर बैठकें नहीं होती हैं, तो यही बात होती है कि चर्चा नहीं होती है, विचार-विमर्श नहीं होते हैं और बहुत ही जल्दबाजी में हम लोग अपने कानून बनाकर चर्चाओं को समाप्त कर देते हैं। इस संदर्भ में देश की विधायिकाओं के पीठासीन अधिकारियों की बैठकों में कई बार चर्चा हुई। 1996 में दिल्ली में हुई एक बैठक में प्रस्ताव भी पारित किया गया। जिसमें कहा गया कि तमाम विधायिकाओं में होने वाली बैठकों की संख्या बहुत ही कम है, जिससे सदस्यों को अपने क्षेत्रों तथा लोक महत्व के विषयों पर चर्चा का समय नहीं मिलता है। अतेव सभी विधायिकाओं को इस विषय पर कानून या परंपरा बनानी चाहिए, जिसमें कम से कम अवधि का प्रावधान हो तथा विशेष रूप से उन्हें संसद को Model के रूप में लेना चाहिए।

पुनः शिमला में 1997 में पीठासीन अधिकारियों की बैठक में प्रस्ताव पारित किया गया। जिसमें कहा गया कि निश्चित तौर पर कार्यपालिका की विधायिका के प्रति जवाबदेही तय करने के लिए, सरकार के कार्यों की समीक्षा जरूरी है, जिसके लिए आवश्यक है कि राज्यों की विधायिकाओं की बैठकें छोटे राज्यों के मामलों में 60 दिन और बड़े राज्यों की विधायिकाओं के लिए बैठकें कम से कम 100 दिन हों। सत्र का आमंत्रण संविधान के अनुच्छेद 174(1) की मात्र औपाचारिकता नहीं होनी चाहिए।

चंडीगढ़ में सन् 2001 में पुनः एक रिपोर्ट एडोप्ट की गई, जिसका नाम था Procedural uniformity and Better Management of the time of the House, जिसमें फिर से छोटे राज्यों के लिए सत्र के लिए 60 दिन तथा बड़े राज्यों के लिए 100 बैठकों का प्रावधान किया गया।

जस्टिस वेंकटचैल्लैया की अध्यक्षता में गठित 'National Commission to Review the working of the Constitution' ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा कहा था कि संसद और राज्यों को कम से कम बैठकों का प्रावधान करना चाहिए। जिन राज्यों के 70 से कम सदस्य हैं, वहां कम से कम 50 बैठकें होनी चाहिए और जहां इससे अधिक सदस्य हैं, वहां पर 90 दिनों की बैठकें होनी चाहिए। यह अवधि राज्य सभा और लोक सभा के लिए 100 और 120 दिनों की होनी चाहिए।

महोदय, संसद पंडित नेहरू के समय तक एक जीवंत संस्था रही। इसके बाद सरकारों ने समीक्षा और बहस से बचने के लिए तथा मनमाने ढंग से नीतियों को लागू करने के लिए सत्र को छोटा करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से आज संसद सदस्यों को विधायी, नीतिगत, लोक महत्व और अपने-अपने क्षेत्रों के मुद्दों पर बोलने के लिए समय ही नहीं मिल पाता है। संसद धीरे-धीरे कार्यपालिका का अंग बनती जा रही है। संसद प्रजातंत्र का सबसे बड़ा मंच है, जहाँ सौ करोड़ से ज्यादा जनता को अभिव्यक्ति मिलती है। देश की जनता की भावनाओं को प्रतिध्वनित करने के लिए नियमों में तमाम तरीकों के instruments हैं, जैसे Question Hour, Zero Hour, Special Mention, Motions, Calling Attention Motion, Short Duration Discussion और Half-an-hour Discussion, आदि। लेकिन समयाभाव के चलते हम मुद्दों को नहीं उठा पाते हैं और उन पर चर्चा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जब बैठकें ही नहीं होंगी, तो हम चर्चा कहाँ करेंगे! कहाँ हम उन इश्यूज़ को उठा पाएंगे! यही हो पाता है। अब एक नई परम्परा की शुरुआत हुई है कि स्पेशल मेंशंस को भी, जो पहले पढ़ कर कहे जाते थे, जिससे उसका एक भाव बनता था और लोगों के ऊपर उसका एक असर आता था, अब उसे भी

'ले' करा दिया जाता है। प्रश्नों के बारे में पाबंदी, एक लिस्ट में 155 से ज्यादा प्रश्न नहीं, एक सदस्य के हिस्से में एक से भी कम प्रश्न आता है। ये सारी पाबंदियाँ सरकार को मदद करती हैं, ब्यूरोक्रेसी को मदद करती हैं। संसद का जो असली कार्य है कि हम ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल करें, सरकार के कार्यकलापों पर अंकुश लगाएँ, हम उसको नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारी बैठकें ही नहीं होती हैं।

हम लोग प्राइवेट मैम्बर्स बिल्स लाते हैं और उसके आधार पर पॉलिसीज़ बनती हैं। लेकिन जब पॉलिसीज़ बनती हैं, तो उसमें उसका कोई ज़िक्र भी नहीं होता है।

महोदय, आज के दौर में decision making में संसद की भूमिका नगण्य होती जा रही है। शक्तिशाली नेता और पार्टियाँ अक्सर प्रजातंत्र की संस्थाओं को कमजोर करने का काम करते हैं। विधेयकों को 20-20 क्रिकेट मैच की तरह लिया जा रहा है। 23 दिसम्बर 2008 को 8 विधेयक सिर्फ 17 मिनट में पास कर दिए गए। क्या यह संसदीय परम्परा का सही निर्वाह था कि 8 विधेयक 17 मिनट में पास किए गए? इनमें से 3 विधेयक बहुत ही महत्वपूर्ण थे। Criminal Procedure Code (Amendment) 2008 भी इनमें से एक विधेयक था, जिसको लेकर 3 फरवरी, 2009 को बीस लाख से ज्यादा वकीलों ने पूरे देश में हड़ताल कर दी। यह जो जल्दबाजी में कार्य किए जा रहे हैं, संसद की बैठकें नहीं कराई जाती हैं, इससे हम सरकार को निरंकुश करते हैं, ब्यूरोक्रेसी को निरंकुश करते हैं। मैं चाहता हूँ कि इस बिल पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

महोदय, इस संदर्भ में राज्य सभा की भूमिका बहुत ही अहम है। हम लोग राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। हमें राज्य सभा की भूमिका को पुनर्परिभाषित करना पड़ेगा। राज्यों से सम्बन्धित तमाम ऐसे विषय हैं, जिन पर राज्य सभा में बहस अगर ठीक ढंग से हो, तो लोक सभा का भी समय बच सकता है। ऐसे विषय, जो कि राज्यों से सीधे तौर पर जुड़े हैं तथा जहाँ राज्यों को केन्द्र की मदद की अपेक्षा है, हम उनको प्राथमिकता के साथ ले सकते हैं। इससे राज्यों को बड़ी मदद होगी। इन विषयों में Climate Change, Agricultural crisis, Water crisis, River disputes, Environment protection, Rural development, Food crisis, Higher education, SEZ, Land acquisition, Terrorism, Naxal problem, Power आदि राज्यों की तमाम समस्याएँ हैं, जिनमें केन्द्र को मदद करनी चाहिए। यह तभी हो सकता है, जब हम जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप अधिक-से-अधिक समय संसद में दें। हमारी समितियाँ मिनी-पार्लियामेंट हैं। इनकी बैठकों को सरकार गम्भीरता से नहीं लेती है। समितियों की सिफारिशों को दरकिनार कर दिया जाता है। समितियाँ बहुत ही शक्तिशाली संसदीय व्यवस्था है। इसके जरिए हम सीधे जनता से जुड़ते हैं। हमें चाहिए कि हम समस्याओं को समितियों के माध्यम से लें। समितियों की जो recommendations आती हैं, उन पर सरकार सही रूप से विचार करके उन्हें स्वीकार करने में भी न हिचके। हमारे यहाँ कुछ इस तरीके की स्थिति होती चली गई है कि हम नहीं चाहते हैं कि संसद अधिक दिन मिले, क्योंकि जितने अधिक सत्र होंगे, उतनी अधिक समस्याएँ होंगी, उतना अधिक ब्यूरोक्रेसी के ऊपर, सरकार के ऊपर अंकुश होगा। इसका सबसे अच्छा उपाय होता है कि संसद के सत्र कम-से-कम बुलाए जाएँ, जो कि गलत है। इसीलिए मेरा यह विचार है और मैंने इस बिल को पेश किया है कि कृपया आप इस पर विचार करें कि पार्लियामेंट को कम-से-कम 120 दिन meet करना चाहिए और राज्यों म उन्हें कम-से-कम 60 दिन मिलना चाहिए। मेरा यह सुझाव है और मैं यह चाहता हूँ कि इस बिल पर चर्चा करके इसको पास किया जाए। धन्यवाद।

SHRI SHANTARAM LAXMAN NAIK (Goa): Mr. Vice-Chairman, Sir, the Constitution (Amendment) Bill moved by Shri Mahendra Mohan seeks to amend two Articles — 85 and 174 — of the Constitution. Article 85 broadly reads, "The President shall from time to time summon each House of Parliament to meet at such time and place as he thinks fit, but six months shall not intervene between its last sitting in one session and the date appointed for its first sitting in the next session." That means, the period of intervening session has been fixed. But, number of

days has not been fixed. Therefore, Shri Mahendra Mohanji seeks to amend this Article and also Article 174 pertaining to State Legislatures to fix a certain number of sittings. Sir, my initial reaction, after reading the Bill, was this. Why a statutory compulsion? Why not leave it to convention as it happens today. But, there are demerits in the convention. In the sense, the Government of the day may choose to have a lesser number of days of a session. It happens in many State Legislatures. Therefore, my considered view is to support the concept. Let us put it in the Constitution, so that no Government can dilute the relevance of a Legislature, whether at the State level or at the national level. Therefore, in principle, I welcome this Bill.

Sir, Legislatures are the pillars of democracy. Nation runs through Legislatures. Sometimes people say, *"Quaide zyada ho gaye."* Why so much legislation? But, ultimately, the first infrastructure is legislation. Sometimes, you may keep aside legislation and do some good action. But, if legislation is not at its place, nobody is going to listen. Therefore, legislation is very important. There are three Lists in the Constitution. The first one is the Union List, the second one is State List and the third one is the Concurrent List. Legislation enacted or amended as per the subjects mentioned under these three Lists. There are executive orders passed by the Government from time to time. And, there are also schemes of the Government. Schemes are, broadly, executive orders only. They are not legislation. But, they have got the force of law. If we required to discuss and deliberate legislation which is brought before Legislature from time to time, then, a fixed time is required. Whether the time given at present is sufficient or not is to be examined. Therefore, the number of days has to be more and more so that more and more legislation are discussed. Basically, we have sufficient legislation in the country. All the areas have been covered, except the modern ones like electronic things, etc. They required to be covered with new legislation. Or, it we would like to give some benefits in a larger scale like the Employment Guarantee Act, it requires new legislation. Broadly speaking, areas are covered. We do not require much new legislation. At the same time, implementation aspect is also important. But, amendments of even one line or one word to several hundreds of Acts are going to create a big effect on the society at large, because there are many Acts where simple amendment would do miracles. Therefore, the Government has to identify Acts which are faulty. The Government should also identify the Acts which are archaic that required revision. Identify such legislation. If identification is done, then we will see that we require many, many days of Parliament to discuss such legislation. It is because we are not identifying legislation which requires amendment. We feel okay some 7-8 Bills are coming for amendment or enactment, some subjects come for general discussion, some Calling Attention, Short Duration and that finishes our job. But, if we dig into these aspects, then we will find that the time is not sufficient.

Secondly, what we legislate? When we enact some legislation, it is only 30 per cent of law. Sir, 70 per cent contain in rules. So, we have to adopt some practice where by rules are also discussed either along with the bill or at a later stage. If we do not discuss the rules, it means, 70 per cent of a statute is not discussed! ...only thirty per cent is discussed because the Act or the Bill contains only 30 per cent legislation and most of the things are laid down in the rules. So, some practice has to be developed and we will have to take a new initiative whereby rules are also discussed. For this, again, number of Session days has to be more. Then, it has been noticed that whenever we pass any legislation, after the discussion is over, many Members give their amendments, particularly the Members of the Opposition because from the ruling side we normally do not give amendments, but we sometimes do not allow the hon. Members to explain their amendments because debate is over and everybody is tired. But the real content of a view is contained in amendments. Therefore, I would like to urge upon the Government that whenever an amendment is moved by anybody that amendment should be moved and the concerned Member should be given 2 to 3 minutes to explain that amendment. Then, the House may agree or disagree with that. Though the speeches are broad, yet they do not contain the exact things. The exact things are contained in the amendments. But that exact part is not being recognized by us. Therefore, taking this opportunity, I would like to request the Government to give a thought to this.

Then, there is a feeling that if you have more number of Session days, the work of the Government will suffer. It is not so because the Ministers do not remain present all the time, and they need not. Whenever they have got business, they may remain present and rest of the time they are in their offices. Therefore, if the number of Session days is increased the work of the Government will not suffer. It is only psychological because sometimes the bureaucrats may also say, "No; no, you come after one month, first let the Session be over". This is some kind of pretext. So, let the Session and the Government functioning go together. Earlier, I remember, when I was the Member of the other House in 1984, the Budget Session was continuously for two months and three weeks. Now, that system has gone because Standing Committees have come in between. The work is done by the Standing Committees. It's okay, but there is no recognition for the work that is done during that one month in the Standing Committees because there is no coverage and nobody knows what we say there. So, it is not known to anybody that we are also working in the Standing Committees because all the proceedings are indoors. On the contrary, there is ban that until the report is submitted to the Committee one cannot divulge anything outside. Though it is a parliamentary job that we are doing, but our mouth is shut. So, what is the advantage of this exercise? It is better that we resort to the old system where the Budget Session used to be over 2-3 months. I am not saying that the Standing Committees have no utility, but I am just trying to point out that though during that one month also the

parliamentary work is going on but the outside world does not know about it. Therefore, some thought has to be given to this aspect also.

Then, we have got Rules of Business. According to these rules, any matter pending in a court of law cannot be raised in the House. Is it possible? I think, most of the matters that we discuss today are, in some form or the other, in the court of law. It is practically not possible. Therefore, I would like to urge upon the Parliamentary Affairs Minister and others concerned that this rule should be done away with because it creates unnecessary hurdles. You cannot implement it also, if you implement you will not be able to do justice to the people because there may be big issues of public relevance and anybody may go and file a writ petition in the court of law and block the Parliament. If we say that pending matters cannot be discussed in the House, it is very easy to block the discussion. Therefore, such rules which are not practicable should not be allowed to remain in statute books. Then, Sir, I would like to make a minor suggestion regarding Unstarred Questions. We get the replies of Unstarred Questions at 12 o'clock in the office. There is a problem. If the Unstarred Questions are put simultaneously on the Internet — suppose you are not in Parliament, you are somewhere outside — because they are supplied in electronic forms, then it would be quite advantageous. A request was made by me quite some time back but the Ministries supply the electronic data to the concerned Department very, very late, after three, four days. Therefore, forget about the replies by 12 o'clock, even next day or third day they are not available on the Parliament website. Therefore, I urge upon the Minister to do something in this matter.

Then, Sir, Rajya Sabha sits up to five o'clock. I do not know when this convention developed. But Lok Sabha sits up to six o'clock. Similar issues are discussed in both the Houses. Country is one. There are only two Houses. Why do not we sit up to six o'clock?

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Rajya Sabha is elders' House. ...*(Interruptions)*...

SHRI SHANTARAM LAXMAN NAIK: I would suggest that that one hour be used for Private Members. We have got several Bills and Resolutions. Hardly, one Bill is discussed. I have given notices for 70 Bills. In six years time, I do not know whether, forget about two Bills, even one Bill or one Resolution came up for discussion. If this is the case, that means there is some flaw in the days allotted to Private Members' Bill. So, allot this one hour for Private Members. We will all be sitting here and we will be doing our job.

Then, Sir, actually, I was surprised that on the first day itself, a Calling Attention Motion was taken up for discussion. You can look into the records of the past, and you will find that Calling Attention Motion are extinct speeches now. They are gone. So, I would suggest that after every two, three days, one Calling Attention Motion should be admitted. These days, whole Session

goes without any Calling Attention Notices being admitted, maybe, because of several compulsions. Therefore, Calling Attention Notices should also be appropriately considered. Lastly, since Ahluwaliaji, somehow, is finding objections to my statements or getting disturbed, I would like to end my speech. I hope the suggestions which I have made will be considered. Thank you.

श्री एस.एस. अहलुवालिया (झारखंड) : उपसभाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। हमारे विद्वान साथी महेन्द्र मोहन जी इस संविधान (संशोधन) विधेयक, 2008 के द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 85 और अनुच्छेद 174 में संशोधन चाहते हैं। उन्होंने यह जो मंशा रखी है, शायद वह सभी सांसदों की मंशा है, सभी सांसदों की इच्छा है। उन्होंने मुंबई में जिस मुख्य सचेतकों की कांफ्रेन्स का उल्लेख किया है और जिस रिपोर्ट का उल्लेख किया है, उस समिति का मैं अध्यक्ष था और वह रिपोर्ट मेरी बनाई हुई है।

महोदय, आप आर्टिकल 85 और आर्टिकल 174 की बात करते हैं, परन्तु मैं एक मूल सवाल पर बोल रहा हूँ कि हमें पार्लियामेंट क्यों चाहिए? Why do we need Parliament? This is a big question. And, today, the young generation, the present generation is asking why we need Parliament. The answer is, "to legislate — basically, we are law-makers — and to make the Minister and through the Minister, officers and Government servants accountable to Parliament...*(Interruptions)*... and then, monitor the monitoring agencies and regulatory agencies.

Otherwise, there is no monitor for monitoring agencies and regulatory agencies. It is only the Parliament which can monitor. Through the Question Hour, the system started long ago. During the Question Hour, when we ask questions, the Ministry, the Department gives answers. Now, the Right to Information Act came only in 2005. But the provision of the Right to Information Act was already available to us, more or less, not in similar shape but in some other shape. It was available to the Members of Parliament. That right was with us and we were using it. Whenever anybody wants any information from some Department, they approach us; social organisation, any other organisation approach a Member of Parliament and request us to ask a particular question. So, this was about the Question Hour.

Then there is another platform or another forum to draw the attention of the Government. Sir, both the previous speakers, my learned friend, the Mover of the Bill and another learned friend, Shri Shantaram, have enlightened us on it, giving certain information about how many sittings took place earlier and how many sittings are now taking place. My learned friend, Mahendra Mohanji, has given some information about foreign countries also. But why did it decline here? Compare it, Sir. I will just give you a very simple example. I have got the figures published by the Lok Sabha Secretariat during the Golden Jubilee Year. The number of Bills passed and assented to on Administrative Matters was about 322 from 1952 to 2002. Then, on Judicial and Legal matters, this number was 156; and on Constitutional matters, it was 86. But on Constitutional matters, we have, I think, reached about 107 or 108. Then, the number of other

legislations was 112; on financial and economics, it was 1854; on social, this figure was 89; and on others, this figure was 394. So, we have passed Bills in four-five categories. But, Sir, if you see the statistics of our population, at the time when we achieved freedom, the population was 35 crores. Today, it is more than a billion and it is said that every year we produce one Australia, and, in Australia, we are facing a new problem now. So, we can understand that we are not only producing one Australia every year but we are producing so many problems also every year. If you narrate the problems, the comparison between 35 crore and one billion, we should compare whether we have increased our system, our number of seats. It is not only the number of sittings, but it is also the number of representatives. Then, there is literacy percentage. Maybe, the literacy percentage has gone high. Illiterates are less. At the time of freedom, less people were there. But the quality of lives of the people was better. Our people were involved in the Freedom struggle. They had sacrificed their lives for the country. They were real patriots. Today, we are divided in our thinking; we are divided in our language; we are divided in religions; we are divided on caste lines; we are divided on everything. Sir, with literacy, another problem that has arisen is that of unemployment. Now, what has it brought? Unemployment! Atrocities on weaker sections! Human rights violations! Then, we talk of liberalisation and consumerism. These have brought in a lot of competitiveness.

There are some statistics that I came across, Sir. In 1953, the cognizable offences/ incidents were about 6,01,964. Today, they are 19,89,673. The percentage of increase is of the order of 230.5 per cent. I am quoting the 1953 to 2007 figures. Take murder, Sir. The last figure was collected in 1971 and it was 9,802; and till 2007, it came to 32,318 murders per year. Take rape. In 1953, the number of rape incidents was 2487. Today, it is 20737. So, one can compare the figures and find out that every minute or every hour, somebody is being raped. Then, take kidnapping and abduction. This is a new industry, Sir. The number of kidnapping and abduction incidents was 5261 and, in 2007, it was 27561. It is only in the case of two things that the figures had declined, so far as the statistics collected in 1953 and 2007, were concerned. One was dacoity and the other was house-breaking, burglary, सेंध मारकर चोरी करना। At that time the figure was 5579 and in 2007 it was 4579, that is, a difference of -17.9 per cent. In house breaking, the figure at that time was 1,37,379 and in 2007, it was 91,218. This is -38.1 per cent less. Now, why am I quoting these figures? I am quoting these figures to show that the problems have increased, their volume has increased and people's grievances have increased. Ultimately, people approach their representatives seeking justice. I don't have with me figures for cases pending in the lower courts, High courts and the Supreme Court, but in the lower courts, it runs into crores, it runs into lakhs in the high courts and it runs into thousands in the Supreme Court. People who fought for Freedom had dreamt that when they attain freedom, when they attain

4.00 p.m.

Swaraj, they would have access to speedy justice, they would have a society free from all sorts of problems and tension. But no, the society is full of problems and tensions. It is not only our problem, Sir, but there are some other problems which are emanating from outside and falling on us. There are some natural problems also. When we talk about the UN Resolutions, global warming is a new threat. In India, somewhere we are facing drought. The other day, Manipur declared drought; the whole State declared drought. Some other States are also facing the similar situation. But half of Assam is facing floods and half of Assam is facing drought. Similar situation is in Bihar. Full of North Bihar is facing floods and the Central Bihar is facing drought. So, where will they discuss these problems? When we don't increase the time; when we don't legislate; when we don't raise the issues of urgent public importance in the House and when there will be no sittings, where will we raise these issues? That is why we need Parliament. Under Article 74, the Minister is accountable to the Parliament and through the Minister the bureaucracy is also accountable to the Parliament and through that system we monitor the developmental projects. Sir, we are living in an era of new generation. They want new legislations; they want new system to work. But we are still carrying those systems or those laws which were once called by our founding fathers, freedom fighters and those who fought against the British imperialism as draconian laws. These draconian laws still exist. The essence of the draconian law is to delay the justice and to delay the redressal. So, there should be a system where grievances should be heard and something should be done in a positive manner for the redressal of that grievance. But where is that system? Where is that cell working today? It is only when the Parliament discuss that matter. Now what do we say in Parliament? We have limited opportunities like Half-an-Hour discussion, Short Duration discussion, Calling Attention, discussion on motion, Zero Hour and Special Mentions. In the Lok Sabha, there are additional two, that is, No Confidence Motion and Adjournment Motion, and nothing more. Yes, out of this Parliament Chamber we have created about 24 Department-related Standing Committees. What happens? Sir, I was going through the Practice and Procedure of Parliament. There I found although an officer cannot appear in this Chamber, but he can appear to brief the Committee in the committee room. He comes and gives his views. Under the doctrine of ministerial responsibility, an officer is accountable to the Minister and through the Minister he is accountable to the Parliament. But, Sir, you cannot punish a civil servant. Parliament cannot punish a civil servant. You can punish the Government through the No Confidence Motion. You can remove the Government. But, you cannot punish a civil servant. His accountability is governed by another Act. Act is passed by Parliament, but then Chief Vigilance Commissioner is there; the Cabinet Secretary is there; and, disciplinary action committees are there. They will take action. But, you can raise the point here. But, if there is no Parliament, then what? How will

you raise issues? My learned friend, while moving the Bill, said that sometimes, the party gives instructions to their Members to make *hungama*. No party gives this mandate to any Member to make *hungama*. It is the grievances. It is the urgency of that matter which he wanted to raise on the floor of the House and when he does not get an opportunity, he gets agitated. If you allow him to ventilate his views or discuss that matter on the floor of the House and Government comes out with a solution, you will never see an adjournment in the House. You will never see that a Member is jumping into the Well. Nobody feels happy when he goes to the Well, or when he is agitated. No Member feels happy. When Members come from their constituencies and when they give audience to the people and they hear their problems and grievances, they think that they must do something for those underprivileged people who cannot afford to even sit here in the visitors' gallery. So, at least, we should do something for them. But, it is very unfortunate because I was going through this record that since when it has deteriorated. Sir, 1975 was the first time when Emergency was declared. In 1975, sittings came down from 119 to 63. Then, in the next year, it was 98. Then, it was 86. Again, in 1978, it was 115 days. It again came down in 1979 to 66 days. Then, 1988 onwards, it is taking the downward trend. The question is: why? Population is increasing; problems are increasing; unemployment is increasing; crisis situations are more. But, the number of sittings is decreasing. So, if you ask a journalist friend there, he says, "No, these are the Members." They write big articles in the newspapers that they have not allowed the House to function. The Treasury Benches, anybody sitting there, will blame the Opposition...*(Interruptions)*. No, those Benches are also protected, and anybody sitting there always think that they are right and others are wrong. It should not be so. I was thinking that since when we have stopped doing the work of nation building. Now, with every Budget, we bring some new formulae, some new *Yojanas*, some new schemes. But, overall, where are nation building schemes? I am not against NREGA. But, when they said, "Through NREGA, no permanent structure will be constructed". Why? If no permanent structure will be constructed, then, why are you spoiling the man hours of the country, the energy of the country? Is it just to give money? You create permanent structure. You pay money for that. Then only, one can understand that with the money spent from the national exchequer, you have created national asset. But that is not there. That is why, I am saying that whenever we formulate certain schemes or announce certain schemes, it is not discussed threadbare.

Every political party brings an emotional agenda, sometimes in the name of ...*(Interruptions)*...I said, every party. If you want to know the names, I can quote 146 parties. There is no problem. When I am speaking, it means that it includes me also. Sir, all political parties bring emotional agenda. But did anybody try to draw a national priority. What are the national priorities? Every year, we go to the United Nations General Assembly. Whenever any

new covenant, law or treaty is passed, India is the first signatory. We are signatory to 'Health for All'. By 'Health for All', we mean that we will provide medical facilities to the entire population. Have we done that? We are signatory to 'Shelter for All', which means that we will provide houses to everybody. Have we done that? 'Justice for All', have we done that? 'Food for All', have we done that? 'Job for All', have we done that? 'Education for All', have we done that? The answer to all these is in the negative. How will you do it if you do not discuss it in the Parliament? If these national priorities are not drawn and brought on the floor of the House for discussion, how will you do it? You have to do this if you want to build the nation.

Today is an important day. Railway Budget has been announced by the new Railway Minister. The Railway Minister might have announced some important and attractive trains, reduction of train fare and all those things. Just compare what Britishers left and what we have today. How many kilometres of railway line did Britishers left, and, in the last sixty years, how many inches of railway line have we added to that. Just calculate this. Then, you will come to know that you have just converted from meter gauge to broad gauge; from broad gauge to second line; from one line to second line or third line, and, nothing else.

Britishers came here to rule this country and commercially exploit us. They exploited us. They identified the places from where they would take the iron ore. They identified the port from where the ship would go outside India after loading. They identified the places. Take for example, Darjeeling train. Who started this? Britishers started this. Why did they start it? At that time, because the air-conditioners were not there, during summer period, they wanted to shift their capital from one place to second place. Take for example, Shimla train. Who started it? Britishers started this. Kalka Mail was known as a super mail. There is a guideline that when Kalka Mail crosses any subdivision, the Sub-Divisional Manager should be present in the control room because all the *Sahebs* travel in the train.

We must discuss these matters, whether it is the railways, steel, coal, nation development, roads, rivers. Now, there are no waterways although we are called country of rivers. Here rivers are worshipped. In the entire world, except India, no river is worshipped. If you live in the North, the Ganga is worshipped. If you live in the South, the Krishna and the Cauvery are worshipped. If you live in the West, the Godavari is worshipped. And if you live in the area near Gujarat or Rajasthan, the Saraswati is worshipped. It is a country of rivers. But we never thought of interconnecting rivers. We never discussed the matter in the House. Is it not important? The concept of 'Garland Canal' has come several times. But we never discussed it, because we did not have the time to do it.

My humble submission is that this is an important Bill. The Government should assure the House or assure the hon. Member that it will bring the amendment.

Shri Shantaram Laxman Naik read the Article 85, Sessions of Parliament, prorogation and dissolution. It says that the President shall from time to time summon each House of Parliament to meet at such time and place as he thinks fit, but six months shall not intervene between its last sitting in one session and the date appointed for its first sitting in the next Session.

But what is President? Article 74 says that there shall be a Council of Ministers with the Prime Minister at the head to aid and advise the President who shall, in the exercise of his functions, act in accordance with such advice.

What does this mean? That means the wish of the Government will be the wish of the President. So, if the Government does not desire to summon the House, or, to provide time to the House for discussion, you cannot summon the House.

Similarly, it is the State Council of Ministers which aid and advice the Governor. And what is that? The hon. Member was quoting the case of Karnataka. I think that Mahendra Mohanji forgot about his own State, Uttar Pradesh. It sat for less than 30 days. The Assembly of the largest State of the country has less than 30 days of sitting.

Under Article 213 of the Constitution, the Governor can promulgate an Ordinance. You ask any Sugarcane Growers' Cooperative Society, when there is no session, they will issue an ordinance. The House will meet for one day or two or three days, and they will not convert that Ordinance into Bill, and that will lapse. After the conclusion of the session, again, they will issue the same Ordinance with a change in 'a' and 'b.'

The same thing is happening in other States also. States are being run by Ordinances. There is no legislation, because there is no time to pass the legislation. There is no consensus to pass the legislation.

My point is, everybody sitting in this House, whether in this corner or that corner, is interested in nation building. And for nation building, our founding fathers have given us the best forum — Parliament. Parliament is to make laws. Parliament is to discuss, debate and deliberate. Parliament is to control and contain corruption. Ministers are made accountable to Parliament, and, through them, the officers are accountable to Parliament. Parliament is to monitor through the monitoring agency and the regulating agency. But, are we doing that? We are failing in that. We are failing in that. And the most important duty in this is of the ruling party. The ruling party must come forward with a Constitution Amendment where it should say that we are amending article 85 and fixing up the sittings as 120 days minimum in Lok Sabha and Rajya Sabha, and in Assemblies, 90 days minimum. That should be fixed. And, that is the recommendation not only of the Chief Whips' Conference, but also, I think, of the Presiding Officers' Conference. There also, they have discussed and deliberated on it.

With these words, Sir, I once again thank you for having given me an opportunity to speak on a very important Bill.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Now, Shri Rajniti Prasad. Not here. Shri Matilal Sarkar.

SHRI MATILAL SARKAR (Tripura): Sir, thank you very much. Sir, first of all, I would like to commend Mahendra Mohanji for bringing forward a very important matter in the House and to rouse us to see that we all stand by in one voice so that the Parliament session may be made meaningful.

Sir, we have numerous problems. We come from States. This is the Council of States. Every State is particular about its own problems. The problems of the North-East may not coincide with the problems of Punjab or Tamil Nadu. When we come here, we want to ventilate the views of the people, their sufferings and their day-to-day life references. We like to bring forth them here. But, what happens is, when we rise to speak, from the Chair, very often, we are cautioned that we must conclude within five minutes.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): I will not say that today. Today, I will not say it.

SHRI MATILAL SARKAR: So, Sir, very often, we face this. Sir, I have observed the sittings in the other House. They are very large in number and while watching their speeches on television, I have seen that they have to conclude in 2-3 minutes. I think, they are more knowledgeable than us in that matter. In this way, actually, we cannot properly ventilate what we want to speak.

Sir, the House has various forms or practices for deliberations by the Members. These are Calling Attention, putting supplementaries, Short Duration Discussion, Special Mentions and, of course, in the other House, the scope of bringing No Confidence Motion and all these things. Sir, I have seen that while supplementary questions are being put to the Ministers, we always raise our hands. Sir, I am on the Food and Public Distribution Committee. So, whenever I have seen that the particular question is very pertinent for me, because I deal with the same there in the House, I find that several Members have raised hands, but the hon. Chairman or the Vice-Chairman or the Deputy Chairman are not supposed to know who belongs to which Committee, and, thereby, the chances of some of us are lost. And it is lost for ever, Sir. It is lost for ever, and I have seen that everybody has raised questions but my point remains unexposed. So, by this way, we miss, and we let others also miss!

Sir, there are incidents in the country, by which the whole country is shaken. There are so many — earthquakes, cyclones, storms, violences, ugly riots, racism, economic issues and sufferings of the people. But we have seen that this Session is not near at hand. And there is no possibility that Session will run. By this way, all these matters or many of these matters go

undiscussed. And when the Session comes, situation changes; new things come in the front and those very important matters become the matters of the past. Situation has changed, and when the Session runs, then, the current affairs only come to the fore. That is why many of the matters by which the whole nation is shaken and which affects the lives of the people also, but the Parliament is not allowed to discuss, we do not get the scope to discuss. Sir, what we have seen in the few months ahead is, in the House, there was a sort of, what should I say, Sir, restlessness in this House, and also in the other House, due to some political chaos. But what I have seen is that by taking advantage of the situation, the Government has taken the opportunity to get the Bills passed without discussion! I do not blame the Government because every Government may take the opportunity like this. But, this is, actually, what we have seen in the papers that here, in the House, and in the other House also, just in 17 minutes, eight Bills have been passed! The news has come like this; I do not know how far it is correct. And, amongst the Bills, there have been important Bills. They are important Bills, but the Bills have been passed! So, we could not give our views; Members could not give their views, their own views or the views of their party; nothing could be given. And by voice votes, the Bills are getting passed! And after three years it may happen that some amendment comes. But, at that time, we shall not be there; some new Members will come and will give their own views, their own thinking!

Sir, see what happens to the Special Mentions! We, the Members, bring very important matters in the House through our Special Mentions. and if one is allowed to read out his or her Special Mention, everybody in the House can understand the meaning or the significance of that Special Mention. But, Sir, what we are allowed to do is "you just lay it!" "You just lay it!" And we rise, and when we rise, the Chair knows that so and so Member is present; so this should be accepted!

Others could not understand what is stated in the Special Mention. I could not know what my colleagues have stated in their Special Mentions. That is why the true meaning of the legislation....

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P. J. KURIEN): Matilalji, on this issue the leaders of the parties can sit together and bring about a consensus. If you are ready to sit after 5.00 P.M., the Special Mentions can be read also. I think, you can take the initiative for doing that. You can take the initiative for doing that.

SHRI MAHENDRA MOHAN: If we meet more often, we will automatically get more time.

SHRI MATILAL SARKAR: They come in the papers. They come in the parliamentary apers. But my point is not this. If I read it out in the House, others can understand it and they would take interest in it, and thereby the subject-matter can get enriched. That scope is lost.

Sir, the session of the House is not getting the importance it deserves and it is not bearing the fruits in the right way. I should say that its importance is sometimes ignored and very often the Parliament is bypassed. Take, for example, the promulgation of ordinances. This is the best instance where the Parliament is bypassed. Sometimes the Government takes decisions overnight when the Parliament is scheduled to meet on the next day. We have seen that at midnight the prices of petrol and diesel have been increased. In the morning the Parliament was going to sit and at midnight this price hike had taken place. By these acts actually the Parliament is getting bypassed. This should not be there. We should not belittle the importance of the House. What is the lacuna? There is a lacuna.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P. J. KURIEN): Matilalji, your party's time is eight minutes. You have taken twelve minutes.

SHRI MATILAL SARKAR: I am concluding. Lacuna is there. We don't get time for discussion. The Parliament sits for 20 days or 25 days. It is like that. Sometimes the Parliament gets adjourned before the schedule. As a result of this, the things that we want to bring here or the opinions, the sufferings and the views of the public which we would like to ventilate here, we can't do in the right way. That is why the session should be in its normal form. Actually, a session should be, at least, for 30 days. This is customary. That should be maintained at any cost. By bringing forward this Bill hon. Member, Shri Mahendra Mohan, has given us an opportunity to bring it again to the knowledge of the Government. While preparing for the Budget Session, they should consider all these points.

With these words, I thank you and conclude.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Thank you very much, Matilalji. Shri Brij Bhushan Tiwari.

श्री बृजभूषण तिवारी (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं श्री महेन्द्र मोहन के इस विधेयक का पूरी तरह से समर्थन करता हूं, क्योंकि माननीय सदस्यों को इस विधेयक के जरिए, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर अपनी राय प्रकट करने का मौका मिला है।

आज हम देख रहे हैं कि दिनों-दिन लोकतंत्र में लोक सभा, राज्य सभा या राज्य की विधानसभाओं का महत्व घटता जा रहा है। अभी हमारे माननीय सदस्य ने ठीक ही कहा कि एक तरफ देश की आबादी बढ़ रही है, हमारी समस्याएं दिनों-दिन बढ़ रही हैं, उसी के साथ ही साथ यह बड़ी ही विचित्र और आश्चर्यजनक स्थिति है कि हमें अपनी समस्याओं को लेकर बहस करने का मौका नहीं मिलता है। मान्यवर, यह लोकतंत्र बुनियादी तौर पर बहस मुबाहिसे की ही एक व्यवस्था है। यह तर्क-वितर्क है और तर्क-वितर्क के जरिए ही हम सच्चाई तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। सत्य क्या है, सच्चाई क्या है, उसे जानने की तरफ हम बढ़ते हैं। यह जो संसद है, इस संसद के पीछे मूल भावना यही है कि इस संसद में जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि आते हैं, इसीलिए संसद के बारे में कहा गया है कि संसद देश की जनता के अरमानों और उसकी इच्छाओं का आईना है कि जनता के अंदर क्या अरमान हैं, जनता की क्या समस्याएं हैं, जनता की क्या परेशानी है। जनता के द्वारा निर्वाचित सदस्य संसद में पहुंचता है, संसद में आता है तो यह उसका दायित्व होता है कि वह जनता की

समस्याओं को सदन में उठाए, उसकी चर्चा उठाए, क्योंकि सदन के जितने भी नियम हैं, उन सारे नियमों का एकमात्र उद्देश्य है कि विभिन्न तरीकों से इन नियमों के अंतर्गत, जो लोक महत्व के विषय होते हैं, हम उन विषयों को उठाते हैं। क्वेश्चन ऑवर से सदन शुरू होता है। क्वेश्चन ऑवर में एक घंटे का समय है और उस क्वेश्चन ऑवर में विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। मंत्री की बाध्यता होती है कि वह उसका जवाब दे। यदि सदस्य जवाब से संतुष्ट नहीं होते हैं तो उसके भी नियम हैं। उस पर बहस या अल्पकालिक चर्चा उठाई जा सकती है। इसके जरिए सरकार के क्रियाकलापों का पर्दाफाश हो जाता है,उसके क्रियाकलाप उजागर हो जाते हैं, जनता के सामने आते हैं। यही लोकतंत्र की बुनियादी बात है कि सरकार अंधेरे में काम नहीं करे, सूरज की रोशनी में काम करे। देश के हर नागरिक का यह अधिकार बनता है कि वह सरकार की सारी कार्यवाहियों की पूरी जानकारी उसे हो और वह जानकारी हासिल करने का एकमात्र जरिया या एकमात्र संस्था संसद है। इसलिए यह कहा जाता है कि संसद के सत्र बढ़ने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए। परंतु अभी माननीय सदस्यों ने कहा और अभी जो आंकड़े हमारे पास हैं, 1952 से लेकर 2008 तक के, आप यह समझिए की शुरू में 103, 137 और 139 सिटिंग्स हुईं। 1955 में 139 लोकसभा की सिटिंग्स हुईं और 111 राज्य सभा की सिटिंग्स हुईं, परंतु जैसे-जैसे समय बीतता गया, स्थिति इतनी दयनीय हो गई कि राज्य सभा की सिटिंग्स 60 या 65 पर आ गई और लोक सभा की सिटिंग्स 46 तक पहुंच गई। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि 46 दिन में क्या होगा। पहले तो कमेटी व्यवस्था नहीं थी तो बहुत से विभागों की जो अनुदान मांगें होती थीं, वह गिलोटिन हो जाती थीं, पास ही नहीं होती थीं। पहले बहुत से कॉलिंग अटेंशन लाने के लिए बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती थी। वे एडमिट ही नहीं होते थे। बड़ी मुश्किल से कहीं, एक, दो या तीन और वह भी अगर मंत्री जी चाहें, मंत्री जी की राय होगी तभी आपका कॉलिंग अटेंशन स्वीकृत किया जाएगा।

क्योंकि सरकार और सरकार की नौकरशाही, ये दोनों बहस से भागते हैं। कोई अपनी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता। इस संसदीय लोकतंत्र में जो accountability और transparency है, पारदर्शिता और उसका दायित्वि, इन दोनों से यह सरकार और सरकार की नौकरशाही भागने की कोशिश करती है। इसलिए इनकी कोशिश होती है कि सदन कम-से-कम समय का हो।

मान्यवर, सबसे बड़ी बात यह भी है कि जो भी सत्र होते हैं, उनमें ज्यादा समय सरकारी कार्य होते हैं। गैर-सरकारी काम के लिए मुश्किल से शुक्रवार को आधा दिन मिलता है। सदस्यों के जो अधिकार होते हैं, उन अधिकारों में कटौती होती है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि हमें सचमुच लोकतंत्र को जीवंत बनाना है, क्योंकि लोकतंत्र में ही जितनी भी सारी राजकाज चलाने की व्यवस्थाएँ हैं, उन व्यवस्थाओं में आज भी लाख खामियों के बावजूद लोकतंत्र ही सबसे अच्छी और सबसे सुविधाजनक व्यवस्था मानी गई है। दुनिया में इसका आज भी कई तरीके से विरोध हो रहा है, इसमें तमाम प्रकार की विकृतियाँ आ रही हैं, पर इन सबके बावजूद आज भी यही सबसे ज्यादा स्वीकार्य है। इस लोकतंत्र में अगर संसद बिल्कुल पंगु बन जाए, संसद बिल्कुल कमजोर बन जाए, संसद का जो प्रभाव होना चाहिए, वह प्रभाव बनने की बजाय घट जाए, तो इस लोकतंत्र का मतलब क्या है! लोकतंत्र का मतलब तंत्र भर रहेगा, लोक गायब हो जाएगा। जनता की कोई हिस्सेदारी, जनता की कोई साझेदारी होनी चाहिए। अगर जनता की हिस्सेदारी या जनता की साझेदारी नहीं रहेगी, तो सरकार की भी कोई जवाबदेही नहीं रहेगी। संसद से ज्यादा खराब स्थिति विधान सभाओं की है। चूँकि यह हमारी सबसे आदर्श संस्था है, अगर लोक सभा के दिन घटेंगे, अगर राज्य सभा के दिन घटेंगे, तो आप समझ जाइए कि यह बिल्कुल छुआछूत की बीमारी है और इस छुआछूत की बीमारी का असर विधान सभाओं पर भी पड़ता है। राज्यों के अन्दर जो तमाम ऐसे लोक महत्व के विषय होते हैं किसानों से सम्बन्धित, व्यापारियों से सम्बन्धित छात्रों से सम्बन्धित, कर्मचारियों से सम्बन्धित, ये तमाम सवाल जनता की नजर से ओझल हो जाते हैं, सरकार कोई जवाब नहीं देती है।

मान्यवर, हम देख रहे हैं कि जो सवाल किए जाते हैं, जो प्रश्न उठाए जाते हैं, उन सवालों का कितना evasive reply यानी सत्य से अलग हटने की और उसको गोल-मटोल तरीके से, ठीक या ठोस जवाब देने से सरकार और सरकार की नौकरशाही कतराती है। समयाभाव के कारण हम उस पर बहस नहीं चला सकते। इसलिए मैं यह मानता हूँ कि इस पर बहुत ही गम्भीरता से विचार होना चाहिए। देश में विचार हो रहा है। तमाम समाचार-पत्रों में बहुत अच्छे-अच्छे articles आ रहे हैं। लोग अपनी राय व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि यह केवल संस्था का ही अपमान नहीं है, संस्था के अपमान के साथ-ही-साथ पूरी राजनीति का अपमान है। आज जिस तरीके से चुनाव हो रहे हैं, आज जिस तरीके से हमारे प्रतिनिधि चुने जा रहे हैं, जिस तरीके से हमें सुविधाएँ प्राप्त हो रही हैं और उसका नतीजा कुछ नहीं निकल रहा है। अगर आज की राजनीति के जरिए हम जन समस्याओं का निदान या समाधान नहीं ढूँढ़ पाएंगे और लोगों का विश्वास राजनीति से या लोकतंत्र से उठ जाएगा, तो उसके कितने भयावह परिणाम होंगे, हम इसकी कल्पना नहीं कर सकते। आज हमारे देश के अन्दर चाहे वह पूर्वांचल का इलाका हो, चाहे उत्तरांचल का इलाका हो, चाहे आदिवासी इलाके हों, आज उन इलाकों में जिस तरीके से वहाँ के लोग हथियार उठा रहे हैं, वहाँ के लोग हिंसा पर उतारू हैं, अगर आप केवल बल के जरिए, केवल ताकत के जरिए, केवल पुलिस के जरिए उस असंतोष को, उस आवाज़ को दबाने की कोशिश करेंगे, तो उसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा। लेकिन अगर हम वहाँ के लोगों की समस्याओं को उठाने की कोशिश करें, तो हमारे पास समय ही नहीं है।

सरकार के पास भी समय नहीं है कि उनकी समस्याओं पर कोई विचार करे अथवा उनको जानने की कोशिश करे। धीरे-धीरे आम लोगों में यह विश्वास पैदा हो रहा है कि संसद का माने कुछ नहीं। यहां केवल कोरी, निर्गुण बहस होती है। न तो इस बहस से अधिकारी डरता है, न भ्रष्टाचारी डरता है और न ही इस बहस से जनता के अंदर हम कोई विश्वास पैदा कर सकते हैं कि इस सदन में मामला उठाने से कुछ नतीजे निकलेंगे। पहले सदन से लोग डरते थे। पहले सदन का बड़ा असर होता था। एमपी का या विधायक का बड़ा असर होता था। अब आप देखिए, आज की अखबारों में एक घटना के तहत आया है कि एक एमपी को माफी मांगनी पड़ी, क्योंकि एमपी साहब के ऊपर इल्जाम था कि उन्होंने एक बैंक के मैनेजर को झापड़ मार दिया। किन परिस्थितियों में वह सब हुआ, उस पर मैं चर्चा नहीं करना चाहता हूं, मगर मैं यह बताना चाहता हूं कि बैंकों में किस तरीके से भ्रष्टाचार है। जो भ्रष्ट कर्मचारी या अधिकारी हैं, उनका जबरदस्त संगठन है और वे आपस में संगठित हो जाते हैं। आज हमसे कोई नहीं डरता है। मिनिस्टर से, विधायक से, एमपी से कोई नहीं डरता है, परन्तु अगर हम जन समस्याओं को लेकर किसी अधिकारी के पास जाएं तो कहने को प्रोटोकोल में हमारी स्थिति सेक्रेटरी के बराबर है। लेकिन अगर आप असलियत में देखना चाहें, तो जो कलेक्टर है, वह भी अपने को एमपी से सुपीरियर मानता है ...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: दारोगा भी बड़ा मानता है।

श्री बृजभूषण तिवारी: माननीय सदस्य ने ठीक कहा कि दारोगा भी अपने को बड़ा मानता है। अब आप बताएं कि हमारे सामने क्या विकल्प है? सदन में हम जा नहीं सकते, विधान सभाओं में ये मसले उठ नहीं सकते और अगर उठते भी हैं तो सरकार उन पर कोई कार्यवाही करने को तैयार नहीं है। सरकार कोई कार्यवाही नहीं कर सकती, सदन में मुझे मामला उठाने का कोई अवसर नहीं है, कहीं पर कानून इतने पेचीदा हैं कि उन कानूनों से कोई नतीजा निकलने वाला नहीं है। अगर अपने मतदाताओं का अथवा जिस जनता का हम प्रतिनिधित्व करते हैं, उनकी परेशानियों का निदान नहीं ढूंढ़ पाते, उनको न्याय नहीं दिलवा पाते, उनको उनका हक़ नहीं दिलवा पाते तो आखिर हमारे पद पर रहने का या सदन में सदस्य बने रहने का क्या औचित्य है? इसका नतीजा यह निकलता है कि इसकी चर्चा तो कभी नहीं होती कि सदन की बैठकें कम हो रही हैं, परन्तु सबसे ज्यादा चर्चा यह होती है कि संसद सदस्यों को सुविधाएं कितनी हैं, उनका भत्ता कितना है, टेलीफोन की कितनी सुविधा दी गई, बिजली की कितनी सुविधा दी गई और फिर उसका मुक़ाबला दुनिया के

दूसरे देशों से अथवा जो गरीब लोग हैं, उनके स्तर से किया जाता है। यानी, चारों तरफ से एक सोची-समझी साजिश के तहत यह विचित्र प्रवृत्ति पूरे देश में पनप रही है कि जो राजनीतिकर्मी हैं अथवा जो राजनैतिक दलों के नेता हैं अथवा राजनैतिक दल हैं, उनका चरित्र हनन करो। उनके प्रभाव को, उनकी प्रतिष्ठा को घटाने की कोशिश करो। इन सबसे आज पूरे देश के अंदर एक प्रकार से डीपॉलिटिकल, अराजनैतिक वातावरण पैदा हो रहा है। जब से देश में इस उपभोक्ता संस्कृति ने जन्म लिया है, तब से लोगों में, विशेषकर जो नई उम्र के लोग हैं, उनमें कोई वैल्यूज़ नहीं रह गई हैं, कोई मूल्य नहीं रह गए हैं।

आज ही मैंने सदन में एक मामला उठाया था कि गांधी जी के बारे में भी ऊट-पटांग या अभद्र टिप्पणी की जाती है। क्यों की जाती है? गांधी का क्या मतलब है? गांधी का मतलब है - अहिंसा, गांधी का मतलब है - सत्य, गांधी का मतलब है - अपरिग्रह, गांधी का मतलब है - किस प्रकार से सार्वजनिक जीवन की शुचिता बनी रहे। जब देश आजाद हुआ तो एक अमरीकी पत्रकार ने गांधी जी से पूछा कि जब देश आजाद होगा तो देश का प्रधान कौन होगा? गांधी जी ने कहा कि अगर मेरा बस चले तो मैं चाहूंगा कि मेरे आश्रम में जो झाड़ू लगाती है, उसकी लड़की देश की प्रधान बने। उस विदेशी पत्रकार ने कहा कि आप गज़ब के आदमी हैं। आपके पास पंडित जवाहर लाल नेहरू हैं, आपके पास डॉ. राजेन्द्र प्रसाद हैं, आपके पास सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं और एक से एक पढ़े-लिखे विद्वान लोग हैं और आप कहते हैं कि आपके आश्रम में झाड़ू लगाने वाली की लड़की को आप देश का प्रधान बनाएंगे।

इस पर गांधी जी ने कहा कि इसके लिए शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने केवल तीन गुण बताए थे। उन्होंने कहा था कि पहला गुण यह हो कि उसकी integrity beyond doubt हो। दूसरी बात यह है कि वह शरीर और मन से शुद्ध हो और उसका कलेजा मजबूत हो। She should be of stout heart. इसके अलावा वह incorruptible भी हो। किसी भी कीमत पर उसको भ्रष्ट न किया जा सके। ...**(समय की घंटी)**... उन्होंने उसको और ज्यादा एक्सप्लेन किया कि उसमें सीता की आँखों की वह चमक होनी चाहिए जिससे कि कोई रावण भी उसे छूने की कोशिश न कर सके। ये गांधी के मूल्य हैं। जो व्यावहारिक जीवन है या जो लोग आज की राजनीति को सेवा के बजाय धन और प्रतिष्ठा कमाने का जरिया बनाना चाहते हैं, वे लोग आज हमारे ऐसे राष्ट्रीय पुरुषों का और ऐसे मूल्यों की हँसी उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं। यह सिलसिला जब शुरू होता है तो आज वही सिलसिला संसद से, वही सिलसिला राजनीति से, वही सिलसिला जन प्रतिनिधियों के चरित्रहनन और उनके मूल्यों को घटाने से होगा। अगर यह स्थिति बन जाएगी तो यही नौकरशाह और देश के यही भ्रष्ट पूंजीपति अपने निजी लाभ और अपने निजी स्वार्थ के लिए इस देश को ही विदेशियों के हाथों में बेच देंगे। ...**(समय की घंटी)**... इस पर अंकुश लगाने का एक मात्र जरिया यह है कि हम खुली बहस करें, हम संसद की गरिमा को बढ़ाएँ तथा हम संसद के अधिकारों को बढ़ाएँ। ये अधिकार और गरिमा तभी बढ़ सकती है जब हम इसकी ज्यादा-से-ज्यादा सिटिंग करें और संसद सदस्यों को, जनप्रतिनिधियों को लोक-महत्व के विषयों को उठाने का भरपूर मौका दें। मैं इसीलिए इस बिल का समर्थन करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि अमेंडमेंट लाया जाए और इसे सरकार स्वीकार करे कि कम-से कम 120 दिन संसद चले और 60 दिन विधान सभा चले। मैं इन्हीं शब्दों के साथ इस बिल का समर्थन करते हुए अपनी बात खत्म करता हूँ। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री मोहम्मद शफी (जम्मू और कश्मीर): उपसभाध्यक्ष जी, यह जो बिल आईन की तरमीम के हवाले से आज इस ऐवान में पेश हुआ है, इसके अग़राजो मकासिद पर नज़र डालें तो एक बात साफ हो जाती है कि गुजिश्ता 60 वर्षों से ज्यादा हमारे इस पार्लिमानी निजाम में बजाए बेहतरी आने के, बजाय इसके एतबार बढ़ने के, इसके ऐतबार में आवाम की नजरों में भी और हिज्बे इख्तिलाफ़ और हिज्बे इक्तिदार की नज़रों में भी इसकी अहमियत घट गई है। अगर आईन के बनने के बाद लोक सभा की और राज्य सभा की भी 110 सिटिंग्स होती थीं, तो अब उनकी 80 सिटिंग्स तक ही होती हैं। 80 सिटिंग्स ही इस साल में होंगी, लोक

5.00 p.m.

सभा की भी और राज्य सभा की भी। यह एक बड़ा संजीदा मसला है। इलेक्शन के वक्त या इलेक्शन के बाद सिर्फ इतना कहना ही काफी नहीं है कि हम दुनिया की एक बहुत बड़ी जम्हूरियत हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बिलाशुबा हम दुनिया के बड़े जम्हूरी मुल्क होने का दावा करते हैं, लेकिन जम्हूरी मुल्क पर आवाम का एतबार बढ़ाने से ही जम्हूरियत मुस्तहकम हो सकती है, जम्हूरी निजाम मुस्तहकम हो सकता है। यहाँ पर आए दिन हम बेहतर निजाम-ए-हुकूमत या good governance का राग भी अलापते हैं। लेकिन कॉल और फेथ, जिसको हिंदी में कहते हैं - करनी और कथनी में कितना अंतर है, कितना फर्क है? वह आप जमीनी सतह पर देखेंगे, आवाम की सतह पर देखेंगे। आप यहां पर क्या मुबाहिसे करते हैं? बहुत कम लोगों को, बावजूद इस बात के, कि आज लोगों के पास टेलीविजन और रेडियो की सहूलियतें दूर-दराज इलाकों तक भी मौजूद हैं, वे तफरीही प्रोग्रामों में ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं, आपकी इस निजामे-हुकूमत के चलने में और सबसे अदारे में जो मुबाहिसे होते हैं, उनकी दिलचस्पी आज इसमें बहुत घट गई है। बहुत कम लोग हमने देखे हैं, पढ़े-लिखे भी, सियासी मामलात में दिलचस्पी रखने वाले, वे समझते हैं कि क्या देखना है पार्लियामेंट के इजलास की कार्रवाई, वहां तो यह हंगामा होगा, या वाकआउट होगा, कोई संजीदा बहस तो होगी नहीं। जो कानून आएगा, उस कानून पर मुबाहिसे की बजाय, जल्दी में वह कानून जो है, पास कर दिया जाएगा। ये मामलात ऐसे हैं, जिनको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, न हमें नजरअंदाज करना चाहिए। जिनकी मजबूती का हम रोज कहते हैं कि अदारे मजबूत होंगे, तो निजामे हुकूमत मजबूत होगा, बेहतर निजामे हुकूमत होगा। जो आवाम की फलाहो-बहबूद के लिए जो भी पालिसियां और प्रोग्राम यहां से बनकर निकलेंगे, वह आवाम तक पहुंचेंगे उनके फवाईद, लेकिन जब जवाबदेही का अमल ही नहीं होगा, जवाबदेही का अमल तो तभी है, जब यहां पर तमाम मामलात, जिनके ऐलानात किए जाएं, जिन पालिसियों को यहां बयान किया जाय, अच्छी पालिसियां, उनकी कितनी अमलआवरी होती है, वह लोगों तक ऐसे पहुंचे कि पार्लियामेंट में इस पर बहस हुए, जो भी ऐलानात हुए हैं, उन पर अमलआवरी के हवाले से हुकूमत क्या कर रही है, वह जवाबदेह है आवाम के।

हम पिछले दस, बीस, तीस साल से इस कार्यवाही को देखते आए हैं, और पिछले छह साल से भी देख रहे हैं, अब तो पार्लियामेंट का बाजाब्ता टेलीविजन पर भी यह मामला दिखाया जाता है। आम राय तो यही बनती है कि जवाबदेही जो है, हिज्बे इक्तिदार अपने आपको जवाबदेह ही नहीं समझता है पार्लियामेंट के सामने, किसी तरीके से वह टालने की कोशिश करता है और हिज्बे इख्तिलाफ यह समझता है कि अगर उनकी कोई खबर मीडिया में आनी है तो उसके लिए सिर्फ हंगामा जरूरी है। अगर वह हंगामा नहीं करेंगे, कोई संजीदा बहस करेंगे, तो खबर नहीं बनेगी। हिज्बे इक्तिदार ने भी अपनी सोच में तब्दीली लानी है, हिज्बे इख्तिलाफ ने भी अपनी सोच में तब्दीली लानी है। सबसे बड़ी बात यहां ऑनरेबल मैम्बर ने कही, एक वक्त था कि पार्लियामेंट में जो भी मैम्बर, चाहे लोक सभा हो या राज्य सभा हो, निहायत ही जिम्मेवारी से अपनी बात कहता था। चाहे हिज्बे इक्तिदार को कोई मैम्बर बात उठाता था, या हिज्बे इख्तिलाफ का मैम्बर ही किसी मसले पर यहां बात करता था, उसका निहायत ही संजीदा नोट लिया जाता था और आवाम को भी पता चलता था कि इस बारे में क्या कार्यवाही हुई। तो बड़े-बड़े मसायल के बारे में भी खामोशी को ही बेहतर समझा जाता है। गुज़िश्ता दिनों से हम यहां देखते हैं, दो अहम मामलात यहां पर जेरे-बहस आए। वह अहम इस लिहाज से हैं कि उनके असरात आवाम के जेहन पर पड़ने वाले हैं। एक तो यह था कि किसी वजीर ने - इसमें कितना सच है, यह बात तहकीकात की है.....

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Mr. Shafi, you can continue your speech on the next day when the Private Members' Bill is taken up, please.

श्री मोहम्मद शफी: थैंक यू सर।

جناب محمد شفیع صاحب (جموں اور کشمیر) : اپ سبھا ادھیکش جی، یہ جو بل آئین کی ترمیم کے حوالے سے آج اس ایوان میں پیش ہوا ہے اس کے اغراض و مقاصد پر نظر ڈالیں تو ایک بات صاف ہو جاتی ہے کہ گزشتہ 60 سالوں سے زیادہ ہمارے اس پارلیمانی نظام میں بجائے بہتری آنے کے، بجائے اس کے اعتبار بڑھنے کے، اس کے اعتبار میں عوام کی نظروں میں بھی اور حزب اختلاف اور حزب اقتدار کی نظروں میں بھی اس کی اہمیت گھٹ گئی ہے۔ اگر آئین کے بننے کے بعد 110 سٹنگس ہوتی تھیں، لوک سبھا کی بھی اور راجیہ سبھا کی بھی، وہ اب 80 سٹنگس تک ہی ہوتی ہیں۔ 80 سٹنگس ہی اس سال میں ہوں گی، لوک سبھا کی بھی اور راجیہ سبھا کی بھی۔ یہ ایک بڑا سنجیدہ مسئلہ ہے۔ الیکشن کے وقت یا الیکشن کے بعد صرف اتنا کہنا ہی کافی نہیں ہے کہ ہم دنیا کی ایک بہت بڑی جمہوریت ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ بلاشبہ ہم دنیا کے بڑے جمہوری ملک ہونے کا دعوی کرتے ہیں، لیکن جمہوری ملک پر عوام کا اعتبار بڑھانے سے ہی جمہوریت مستحکم ہو سکتی ہے، جمہوری نظام مستحکم ہو سکتا ہے۔ یہاں پر آئے دن ہم بہتر نظام حکومت یا good governance کا راگ بھی الاپتے ہیں۔ لیکن کال اور فیتھ، جس کو ہندی میں کہتے ہیں، "کرنی اور کتھنی میں کتنا انتر ہے، کتنا فرق ہے"؟ وہ آپ زمینی سطح پر دیکھیں گے، عوام کی سطح پر دیکھیں گے، آپ یہاں پر کیا مباحثے کرتے ہیں؟ بہت کم لوگوں کو، باوجود اس بات کے، کہ آج لوگوں کے پاس ٹیلی ویژن اور ریڈیو کی سہولیتیں دور دراز علاقوں تک بھی موجود ہیں، وہ تفریحی پروگراموں میں زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں، اس کی دلچسپی آج اس میں بہت گھٹ گئی ہے۔ بہت کم لوگ ہم

[] Transliteration in Urdu Script.

نے دیکھے ہیں، پڑھے لکھے بھی، سیاسی معاملات میں دلچسپی رکھنے والے، وہ سمجھتے ہیں کہ کیا دیکھنا ہے پارلیمنٹ کے اجلاس کی کاروائی، وہاں تو یہ ہنگامہ ہوگا، یا واک آؤٹ ہوگا، کوئی سنجیدہ بحث تو ہوگی نہیں۔ جو قانون آئے گا، اس قانون پر مباحثے کی بجائے، جلدی میں وہ قانون جو ہے، پاس کر دیا جائے گا۔ وہ معاملات ایسے ہیں، جن کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے، نہ ہمیں نظر انداز کرنا چاہئے۔ جن کی مضبوطی کا ہم روز ذکر کرتے ہیں کہ ادارے مضبوط ہوں گے، تو نظام حکومت مضبوط ہوگا، بہتر نظام حکومت ہوگا۔ جو عوام کی فلاح و بہبود کے لئے جو بھی پالیسیاں اور پروگرام یہاں سے بن کر نکلیں گے، وہ عوام تک پہنچیں گے ان کے فوائد، لیکن جب جواب دہی کا عمل ہی نہیں ہوگا، جواب دہی کا عمل تو بھی ہے، جب یہاں پر تمام معاملات، جن کے اعلانات کئے جائیں، جن پالیسیوں کو یہاں بیان کیا جائے، اچھی پالیسیاں، ان کی کتنی عمل آوری ہوتی ہے، وہ لوگوں تک ایسے پہنچے کہ پارلیمنٹ میں اس پر بحث ہو، جب بھی اعلانات ہوتے ہیں، ان پر عمل آوری کے حوالے سے حکومت کیا کر رہی ہے، وہ جواب دہ ہے عوام کے۔

ہم پچھلے دس،بیس، تیس سالوں سے اس کاروائی کو دیکھتے آئے ہیں، اور پچھلے چھہ سال سے بھی دیکھ رہے ہیں، اب تو پارلیمنٹ کا باضابطہ ٹیلی ویژن پر بھی یہ معاملہ دکھایا جاتا ہے۔ عام رائے تو یہی بنتی ہے کہ جواب دہی جو ہے، حزب اقتدار اپنے آپ کو جواب دہ ہی نہیں سمجھتا ہے ہے پارلیمنٹ کے سامنے، کسی طریقے سے وہ ٹالنے کی کوشش کرتا ہے اور حزب اختلاف یہ سمجھتا ہے کہ اگر ان کی کوئی خبر میڈیا میں آنی ہے تو اس کے لئے صرف ہنگامہ ضروری ہے۔ اگر وہ ہنگامہ نہیں کریں گے، کوئی سنجیدہ بحث کریں گے، تو خبر نہیں بنے گی۔ حزب اقتدار نے بھی اپنی سوچ میں تبدیلی لانی ہے، حزب اختلاف نے بھی اپنی سوچ میں تبدیلی لانی ہے۔ سب سے بڑی بات یہاں آنریبل ممبر نے کہی، ایک وقت تھا کہ پارلیمنٹ میں جو بھی ممبر، چاہے لوک سبھا ہو یا راجیہ سبھا کا ہو، نہایت ذمہ داری

[]Transliteration in Urdu Script.

سے اپنی بات کہتا تھا۔ چاہےحزب اقتدار کا کوئی ممبر بات اٹھاتا تھا، یا حزب اختلاف کا ممبر ہی کسی مسئلے پر یہاں بات کرتا تھا، اس کا نہایت ہی سنجیدہ نوٹ لیا جاتا تھا اور عوام کو بھی پتہ چلتا تھا کہ اس بارے میں کیا کاروائی ہونی۔ تو بڑے بڑے مسائل کے بارے میں بھی خاموشی کو ہی بہتر سمجھا جاتا ہے۔ گزشتہ دنوں سے ہم یہاں دیکھتے ہیں، دو اہم معاملات یہاں پر زیر بحث آئے۔ وہ اہم اس لحاظ سے ہے کہ ان کے اثرات عوام کے ذہن پر پڑنے والے ہیں۔ ایک تو یہ تھا کہ کسی وزیر نے - اس میں کتنا سچ ہے، یہ بات تحقیقات کی ہے....

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Mr. Shafi, you can continue your speech on the next day when the Private Members' Bill is taken up, please.

جناب محمد شفیع صاحب: تھینک یو سر۔

(ختم شُد)

MESSAGES FROM LOK SABHA

(I) Motion Re: Nomination of Members to the Committee on Public Accounts

(II) Motion Re: Nomination of Members to the Committee on Public Undertakings

(III) Motion Re: Nomination of Members to the Committee on Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes

SECRETARY-GENERAL: Sir, I have to report to the House the following messages received from the Lok Sabha, signed by the Secretary-General of the Lok Sabha:-

(I)

"I am directed to inform you that Lok Sabha, at its sitting held on Friday, the 3rd July, 2009, adopted the following motion:-

"That this House do recommend to Rajya Sabha that Rajya Sabha do agree to nominate seven members from Rajya Sabha for being associated with the Committee on Public Accounts of the House for the term ending on the 30th April, 2010 and do communicate to this House the names of the members so nominated by Rajya Sabha."

2. I am to request that the concurrence of Raja Sabha in the said motion, and also the names of the members of Rajya Sabha so nominated, may be communicated to this House."

[]Transliteration in Urdu Script.